

जालौर जिला कांग्रेस कमेटी

ऑफिस :- बंगला नं. 27, तलवी रोड, आम्पदाया बैरा, योगेशवरी माता मंदिर के सामने, भीनमाल (जालौर)

चुन्नीलाल CL गहलोत

अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विभाग
जालौर

क्र.सं. 131/26

दिनांक : 06/10/26

ज्ञापन

सेवा में,
महामहिम
माननीय राष्ट्रपति महोदया
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली - 110004

विषय : वैज्ञानिक, प्रारम्भिक एवं नीति-निर्माण में उपयोगी जाति जनगणना हेतु **OBC** श्रेणी, मानकीकृत जाति सूची, प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक कोड तथा वैज्ञानिक वर्गीकरण सुनिश्चियण करने के संबंध में।

आदरणीय राष्ट्रपति महोदया,

हम आगामी जनगणना में जातियों की गणना की पद्धति से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह ज्ञापन सादर प्रस्तुत कर रहे हैं।

जाति जनगणना सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक माध्यम तभी बन सकती है, जब देश की प्रत्येक जाति एवं समुदाय की सही, वैज्ञानिक और एकरूप गणना हो।

केवल किसी व्यक्ति से उसकी जाति पूछे लेना पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूछ ही प्रमाणित जाति के अलग-अलग नाम, पर्यायवाची नाम, क्षेत्रीय नाम तथा उच्चारण एवं वर्तनी के अंतर के कारण उसे अनेक अलग-अलग जातियों के रूप में दर्ज न कर दिया जाए।

सही गिनती → सही आंकड़े → सही हिस्सेदारी → सामाजिक न्याय

महामहिम
माननीय राष्ट्रपति महोदया
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली - 110004

विकास
सर्वोच्च

अध्यक्ष
जालौर जिला कांग्रेस कमेटी
(OBC विभाग)

निवास :- बंगला नं. 27, तलवी रोड, आम्पदाया बैरा, योगेशवरी माता मंदिर के सामने, भीनमाल 343029 (जालौर)

हमारी विनम्र माँगें

हम महामहिम से निवेदन करते हैं कि भारत सरकार एवं संबंधित जनगणना अधिकारियों को निम्नलिखित उपायों पर उचित विचार करने हेतु सलाह/निर्देश दिए जाएँ:

1. स्पष्ट OBC श्रेणी

जनगणना प्रपत्रावली एवं गणना पद्धति में Other Backward Classes — OBC की स्पष्ट और अलग पहचान वाली श्रेणी का समुचित प्रावधान किया जाए।

2. प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट बैज्ञानिक कोड

प्रत्येक मान्यता प्राप्त जाति/समुदाय को सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए एक Unique Scientific Caste/Community Code दिया जाए। विशिष्टता तथा सत्यापन के बाद एक ही जाति के प्रचलित पर्यायवाची नाम, क्षेत्रीयक नाम, क्षेत्रीय नाम तथा वर्तनी के विभिन्न रूपों को उसी मास्टर कोड से जोड़ा जाए।

साथ ही नागरिक द्वारा बताए गए मूल जाति नाम को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे व्यक्ति की स्व-पहचान का सम्मान भी बना रहे और आंकड़ों को बैज्ञानिक मानकीकरण भी हो सके।

3. राज्यवार मानकीकृत जाति मास्टर लिस्ट

केंद्र एवं राज्य सरकारों की आधिकारिक सूचियों तथा अन्य प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के लिए बैज्ञानिक रूप से मानकीकृत जाति मास्टर लिस्ट तैयार की जाए।

किसी भी दो नामों को केवल समानता के आधार पर स्वतः एक जाति न माना जाए। उनका एकीकरण आधिकारिक दस्तावेजों, ऐतिहासिक एवं मानवशास्त्रीय प्रमाणों और विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद ही किया जाए।

4. डिजिटल जनगणना प्रपत्र-डेटाबेस निर्माण

डिजिटल जनगणना में गणनाकर्मियों के लिए बैज्ञानिक रूप से तैयार मानकीकृत जाति प्रपत्र-डेटाबेस (कोड/नाम/वर्णिकरण/विवरण सहित) उपलब्ध कराया जाए।

इसमें जातियों के प्रचलित पर्यायवाची नाम, क्षेत्रीय नाम और सामान्य प्रचलित नामों का समावेश किया जाए, ताकि उन्हें संबंधित बैज्ञानिक कोड से जोड़ा जा सके।

यदि कोई वास्तविक जाति/समुदाय मास्टर लिस्ट में उपलब्ध नहीं है तो उसे अलग से दर्ज करने और बाद में विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित करने की व्यवस्था भी हो।

5. राष्ट्रीय बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति

जाति जनगणना की अंतिम सूची तैयार करने से पहले एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, जिसमें निम्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं हितधारकों से परामर्श लिया जाए —

- समाजशास्त्री;
- जनसांख्यिक मानवशास्त्री;
- जनसांख्यिकी विशेषज्ञ एवं सांख्यिकीविद;
- इतिहासकार एवं पुरातत्व/लोक-संस्कृति विशेषज्ञ;
- संबैधानिक एवं सामाजिक न्याय विशेषज्ञ;
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि;
- सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि;
- जाति एवं समुदाय संगठनों के प्रतिनिधि; तथा

राज्य शास्त्री
दिनेश कुमार
अध्यक्ष
जालौर जिला कांग्रेस कमेटी
(OBC विभाग)
28/4

6. जाति एवं सामाजिक संगठनों से राजवार परामर्श

देश के जाति एवं सामाजिक संगठनों के पास अपनी जातियों के स्थानीय नामों, पर्यायवाची नामों, उपाधियों तथा क्षेत्रीय विविधताओं की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

अतः संबंधित जातीय संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को अंतिम रूप देने से पहले राज्यवार संशोधित परामर्श प्रक्रिया अपनाई जाए।

7. तेलंगाना मॉडल जाति सर्वेक्षण के विशेषज्ञों से परामर्श

हम विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि तेलंगाना के सफल जाति सर्वेक्षण, डेटा संकलन, विश्लेषण पद्धति, तकनीकी मॉडल एवं रिपोर्ट निर्माण में जुड़े विशेषज्ञों को परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया जाए तथा उनके अनुभव एवं पद्धति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाए।

इस अनुभव से भारत को ऐसी बैज्ञानिक व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिल सकती है, जो केवल जातियों के नाम एकत्रित न करे बल्कि विश्वसनीय, समेकित (एकीकृत डेटाबेस) और नीति-निर्माण में उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराए।

वैज्ञानिक जाति जनगणना क्यों आवश्यक है?

जाति जनगणना केवल लाखों असंगठित एवं असमंत जाति नामों का विशाल डेटाबेस बनकर नहीं रह जानी चाहिए।

उसका उद्देश्य ऐसा प्रमाणिक बैज्ञानिक डेटा तैयार करना होना चाहिए जिसके आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकारें शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच, प्रतिनिधित्व एवं विकास के अन्य मानकों पर विभिन्न सामाजिक समूहों की वास्तविक स्थिति समझ सकें।

विश्वसनीय जातिगत आंकड़े आरक्षण के भीतर बैज्ञानिक उप-वर्गीकरण (सब-कैटगरीकरण), अत्यधिक वंचित समुदायों की पहचान तथा उनके लिए लक्षित कल्याणकारी नीतियां बनाने में भी महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकते हैं।

गलत आंकड़ों के आधार पर सही नीति नहीं बनाई जा सकती।

अध्यक्ष
जालौर जिला कांग्रेस/कमेटी
(OBC विभाग)

इसलिए गणना प्रारम्भ होने से पहले ही पद्धति को वैज्ञानिक एवं दृष्टिहित बनाना आवश्यक है, क्योंकि डेटा संग्रह के समय हुई गलतियों को बाद में सुधारना अत्यंत कठिन हो सकता है।

महामहिम से हमारी अपील

राष्ट्रीय हिततार्थ, यह केवल पृष्ठ समाज का प्रश्न नहीं है। यह भारत के राष्ट्रीय आंकड़ों की विश्वसनीयता, वैज्ञानिक नीति-निर्माण और सामाजिक न्याय का प्रश्न है।

अतः हम आपके सर्वोच्च संवैधानिक पद से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार एवं संबंधित अधिकारियों को ऐसी जाति जनगणना सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए जिसमें—

स्पष्ट श्रेणी + मानकीकृत जाति मास्टर लिस्ट + वैज्ञानिक कोडिंग प्रणाली + प्रमाणित पर्यवैचायी नाम + डिजिटल डेटा संग्रहण एवं सत्यापन प्रणाली + विशेषज्ञ एवं सामाजिक परामर्श + पारदर्शिता एवं गुणवत्ता नियंत्रण के समुचित उपाय

—को वैज्ञानिक रूप से सम्महित किया जाए।

भारत को केवल जाति जनगणना नहीं, बल्कि एक प्रमाणिक, वैज्ञानिक और डायनामिक जाति जनगणना — जो वर्तमान, भविष्य और नीति-निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा कर सके — की आवश्यकता है, जिससे प्राप्त आंकड़े आने वाली पीढ़ियों के लिए सामाजिक न्याय एवं जनकल्याण की नीतियों का विश्वसनीय आधार बन सकें।

“जाति पूछना ही पर्याप्त नहीं—जाति को सही गिनना जरूरी है।”

इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय पर आपके हस्तक्षेप की सादर अपेक्षा है।

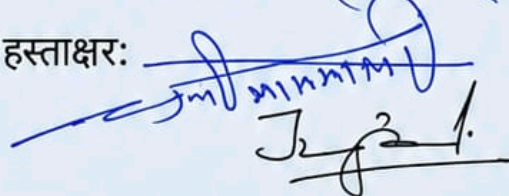
सादर,

सी.एल. गहलोत
अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग विभाग
जालौर जिला कांग्रेस कमेटी

दिनांक: 06/10/26

स्थान: मीनमाल (जालौर)

हस्ताक्षर:



अध्यक्ष
जालौर जिला कांग्रेस कमेटी
(OBC विभाग)